RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 054
दि. 26.11.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

अयोध्या में धर्मध्वज का आरोहण: पीएम मोदी की आंखें नम, राममय हुआ समूचा भारत

(जीएनएस)। अयोध्या। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला वह क्षण मंगलवार को साकार हो गया, जब अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का आरोहण हुआ और पूरा परिसर बहुप्रतीक्षित आध्यात्मिक उत्साह से भर उठा। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाया और विशाल केसरिया ध्वज धीरे-धीरे ऊपर उठता हुआ मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो गया। जैसे-जैसे ध्वज आकाश की ओर बढ़ा, पीएम मोदी की आंखें नम हुईं, चेहरे पर गहन भावुकता साफ दिख रही थी। सामने बैठे साधु-संत भी इस दृश्य को देखकर अपने आंसू रोक न सके। हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों की सांसें थम गईं और ध्वज के शिखर पर पहुंचते ही पूरा अयोध्या 'जय श्री राम' के अदम्य उद्घोष से गूंज उठा। इसी क्षण के साथ राम मंदिर के निर्माण कार्य की औपचारिक पूर्णाहुति भी घोषित हो गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वज फहराने के बाद कहा कि यह ध्वज मात्र एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का राष्ट्रव्यापी संकेत है। उन्होंने इसे उस संकल्प की सिद्धि बताया, जिसकी अग्नि पांच सौ वर्षों तक प्रज्वलित रही। मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सप्तमंडप में जाकर ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगत्स्य, शबरी और निषादराज के दर्शन किए और उन्हें इस समारोह का शाश्वत साक्षी बताया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम भेद से नहीं, भाव से जोड़ते हैं। वे शक्ति नहीं, सहयोग को महत्व देते हैं। राम का चरित्र ज्ञान, विवेक, मर्यादा और पराक्रम का अनुपम संगम है, और इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर भारत आज विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते ग्यारह वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान और श्रमिक सहित हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है और राम की इसी समदृष्टि को राष्ट्र की नीति में उतारा गया है।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के सबसे भावनात्मक हिस्से में कहा कि भारत को अब गुलामी की मानसिकता से पूरी मुक्ति पानी होगी। उन्होंने 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि उसकी जड़ें आज भी समाज की सोच में कहीं न कहीं जीवित हैं। विदेशी वस्तुओं के प्रति आसक्ति और स्वदेशी के प्रति संशय इसी गुलाम मानसिकता की देन है। उन्होंने 2035 तक इस मानसिकता को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इसी सोच के चलते कभी भगवान राम को भी काल्पनिक कहकर विखंडित करने का प्रयास किया गया था। नौसेना के ध्वज को बदलकर देश ने एक बड़े मानसिक गुलाम–प्रतिमान को तोड़ा है, और अब समय आ गया है कि हर क्षेत्र में यही परिवर्तनकारी साहस दिखाया जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमें विकसित भारत का सपना साकार करना होगा। यह तभी संभव होगा जब हर भारतीय अपने भीतर राम के मूल्यों की 'प्राण–प्रतिष्ठा' करे—ईमान, त्याग, करुणा, मर्यादा और न्याय। उन्होंने भावुकता के साथ कहा कि हम भले न रहें, पर भारत रहेगा; यह हमारे संस्कार और संकल्प ही हैं जो आने वाले हजार वर्षों तक भारत को मार्ग दिखाएंगे।

धर्म ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी उपस्थित थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता के मूल मंत्र 'वसुधैव कुटुंबकम' को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत को अब विश्व गुरु बनने की दिशा में अपनी संस्कृति को आचरण में उतारना होगा। उन्होंने कहा कि इस देश का जीवन ऐसा हो कि दुनिया इससे प्रेरणा ले, और धर्म ध्वज का आरोहण इसी दिशा में पहला कदम है।

ध्वज के आकाश में लहराने के साथ ही अयोध्या का वातावरण मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। परंपरा, आस्था, आधुनिकता और राष्ट्रगौरव का संगम एक ही क्षण में साकार हो गया। राममय भारत की यह दिव्य संध्या आने वाले समय में केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उदय की कहानी बनकर याद की जाएगी।

भारतीय सीमा में रहस्यमय घुसपैठ: संवेदनशील क्षेत्रों की रिकॉर्डिंग करते पकड़ा गया चीनी नागरिक, कई देशों की मुद्रा बरामद

(जीएनएस)। बहराइच। इंडो–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर बड़ी सेंध को नाकाम कर दिया है। सोमवार देर रात एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने भारतीय सीमा के भीतर संदिग्ध रूप से घूम रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से विभिन्न देशों की मुद्राएँ, कई मोबाइल फोन और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अति संवेदनशील स्थलों की वीडियोग्राफी बरामद हुई है। सीमा क्षेत्रों में बढ़ती निगरानी और कड़ी जांच के बावजूद इस तरह की गतिविधि ने सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, एसएसबी की 42वीं वाहिनी के उपनिरीक्षक रत्नेश यादव और रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश रावत रात में संयुक्त गश्त पर थे, तभी उन्हें भारतीय क्षेत्र के भीतर एक विदेशी नागरिक संदिग्ध मुद्राओं में दिखाई दिया। रुकने और पहचान बताने को कहने पर वह असहज हो गया और पूछताछ में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। बाद में उसने अपना नाम ल्यू कुजिंग, निवासी हुनान प्रांत, चीन बताया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उसके पास पासपोर्ट, वीजा या किसी भी वैध प्रवेश दस्तावेज का अभाव था, जिससे उसके उद्देश्य पर और अधिक संदेह गहरा गया।

पुलिस उपाधीक्षक प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि भारत में बिना किसी यात्रा दस्तावेज के प्रवेश करना राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े गंभीर अपराधों में आता है। सुरक्षा एजेंसियां कुजिंग के पिछले सफर, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जानकारी खंगाल रही हैं। उसके पास से बरामद देशों की मुद्राओं में चीन, नेपाल और पाकिस्तान की करेंसी शामिल है, जिससे यह आशंका और बढ़ जाती है कि वह कई सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय रहा हो सकता है। पुलिस यह भी तलाश रही है कि भारतीय क्षेत्र में कदम रखने से पहले वह किन लोगों के संपर्क में था और उसकी गतिविधियों की दिशा क्या संकेत देती है।

सबसे चौंकाने वाली जानकारी उसके मोबाइल फोन की जाँच के दौरान सामने आई, जहाँ भारतीय सीमा के संवेदनशील और प्रतिबंधित इलाकों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित मिली। वीडियो देखकर सुरक्षा एजेंसियों में तत्काल अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि इस तरह की सूचनाएँ आमतौर पर जासूसी, अवैध घुसपैठ नेटवर्क या आतंकवाद से जुड़े संगठनों द्वारा इकट्ठा की जाती हैं। एसएसबी कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने पुष्टि की कि पकड़ा गया चीनी नागरिक उन प्रतिबंधित इलाकों की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिन्हें सुरक्षा कारणों से बाहरी व्यक्तियों के लिए पूरी तरह निषिद्ध रखा जाता है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध को तत्काल रुपईडीहा पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहाँ उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के उच्चाधिकारियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है, और यह संभावना जताई जा रही है कि जांच का दायरा अंतरराष्ट्रीय संपर्कों तक फैल सकता है। सीमा पर होने वाली गतिविधियों में हाल के महीनों में बढ़ोतरी ने पहले ही कई सवाल खड़े किए थे, और इस ताजा घटना ने यह चिंता और गहरी कर दी है कि कहीं अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भारतीय सीमाओं और संवेदनशील स्थलों की सूचनाएँ एकत्र कर बड़े षड्यंत्र की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं।

चीन, नेपाल और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का त्रिकोण क्षेत्र पहले से ही संदिग्ध गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में किसी विदेशी नागरिक का बिना दस्तावेज घुस आना और साथ ही प्रतिबंधित इलाकों की रिकॉर्डिंग करना भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। आगे की पूछताछ से यह स्पष्ट होने की संभावना है कि कुजिंग किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था या अकेले ही भारत में गलत इरादों के साथ प्रवेश कर चुका था।

इथियोपिया में कत्लेआम की काली सुबह: उग्रवादियों ने घर-घर घुसकर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को गोलियों से भूना, 40 से अधिक नागरिक मारे गए

(जीएनएस)। इथियोपिया का मेटेकेल जोन शनिवार को ऐसे दर्दनाक नरसंहार का गवाह बना, जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। सुबह करीब 5 बजे जब लोग नींद में थे, तभी ओरोमो लिबरेशन आर्मी (ओएलए) के असंतुष्ट धड़े—जिसे स्थानीय तौर पर 'शेने' नाम से जाना जाता है—के भारी हथियारों से लैस हमलावर बुलेन वोरेडा और बाकुजी केबेले क्षेत्र में धावा बोलते हुए फैल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उग्रवादी समूह घरों के दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुसते गए और महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और मासूम बच्चों तक को गोलियों से छलनी कर दिया। कई घरों में पूरे परिवार खत्म हो गए और कई जगह पाँच-पाँच शव एक साथ निकाले गए। हमले के दौरान उग्रवादियों के पास आधुनिक हथियारों के साथ-साथ चाकू और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार भी थे, जिनसे उन्होंने कई लोगों पर बेरहमी से वार किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर देर रात तक पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और जो भी उनके हाथ लगा, उसे बिना दया के मार डाला। दहशत और खून से सनी इस रात के बाद सुबह होते-होते पूरा इलाका मातम और चीख-पुकारों से भर गया, जबकि भयभीत दिहाड़ी मजदूर और खेतिहर परिवार अपने बच्चों को लेकर जंगलों और दूरस्थ गांवों की ओर भागते देखे गए।

अदीस स्टैंडर्ड पत्रिका में प्रकाशित एक स्थानीय निवासी के बयान के अनुसार, "हमने ऐसा खौफनाक दृश्य पहले कभी नहीं देखा। एक-एक घर में पूरा परिवार खत्म पड़ा था। रोने के लिए भी कोई नहीं बचा।" कई ग्रामीणों ने बताया कि हमलावरों ने रास्तों और पगडंडियों को भी घेर लिया था ताकि कोई भाग न सके, और कई लोगों को भागते समय भी गोली मार दी गई।

स्थानीय प्रशासन ने नरसंहार की पुष्टि करते हुए इसे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाला अत्यंत बर्बर हमला बताया है। बुलेन वोरेडा के उप-प्रशासक शिबेशी बारेडा ने कहा कि उग्रवादी अब भी प्रभावित क्षेत्रों के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय हैं, जिससे सुरक्षा बलों को राहत अभियान चलाने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासक नेमेरा मारू ने बताया कि क्षेत्र की स्थिति अत्यंत अस्थिर है और ग्रामीणों में गहरा भय व्याप्त है। प्रशासन के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दस से अधिक उग्रवादियों को मार गिराया, लेकिन उनका नेटवर्क मजबूत होने के कारण खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस हमले ने इथियोपिया में जातीय उग्रवाद और विद्रोही गतिविधियों की बढ़ती जटिलताओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मेटेकेल क्षेत्र पिछले कई वर्षों से बार-बार हिंसा का केंद्र बना हुआ है, जहाँ राजनीतिक असंतोष, उग्रवादी संगठनों और स्थानीय समूहों के बीच संघर्ष आम नागरिकों पर कहर बनकर टूटता रहा है। प्रशासन का कहना है कि हालिया हमले का पैमाना अभूतपूर्व है और मृतकों की संख्या आगे और बढ़ सकती है क्योंकि कई लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है।

इस त्रासदी के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का आलम यह है कि कई परिवार अब भी अपने घरों में लौटने का साहस नहीं कर पा रहे। इथियोपिया की सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इसे नरसंहार करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और जांच की मांग की है।

मेटेकेल का यह रक्तरंजित हमला फिर साबित करता है कि पूर्वी अफ्रीका में जातीय संघर्ष और उग्रवाद एक बार फिर भयावह रूप लेकर उभर रहा है, और इसका सबसे भारी मूल्य आज भी निर्दोष आम नागरिक ही चुका रहे हैं।

देशभर में बढ़ती हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख़्त— "हर घटना पर नज़र रखना संभव नहीं, पीड़ित हाईकोर्ट जाएं"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में नफरत भरे भाषणों और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली घटनाओं पर जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि देशभर में होने वाले हर हेट स्पीच मामले को वह स्वयं मॉनिटर नहीं कर सकती, और ऐसे मामलों में प्रभावित व्यक्ति को पहले अपने राज्य के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी ऐसे कदम के पक्ष में नहीं है जिससे न्यायपालिका पुलिस तंत्र जैसा व्यवहार करने लगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने तर्क रखा कि बीते कुछ महीनों में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों और आर्थिक बहिष्कार की घटनाओं में तेजी आई है, और कई बार स्थानीय प्रशासन शिकायतें दर्ज करने में भी अनिच्छुक दिखता है। पाशा ने इन घटनाओं को रोकने और केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।

सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हेट स्पीच किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कानून-व्यवस्था राज्यों का विषय है और केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाना उचित नहीं है। इस पर अदालत ने भी माना कि हर शिकायत को शीर्ष अदालत में खींच लाना न्यायिक व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालता है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने सख्त लहजे में कहा— "यह सुप्रीम कोर्ट है, कोई पुलिस चौकी नहीं। जहां घटना घटित हो रही है, वहां का हाईकोर्ट उचित मंच है। अगर किसी जगह पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो अवमानना या अन्य उपायों के लिए भी हाई कोर्ट में ही जाया जाना चाहिए।"

अदालत ने हस्तक्षेप याचिका पर असंतोष भी व्यक्त किया, यह कहते हुए कि इन्हें व्यापक याचिकाओं से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि, पाशा द्वारा असम के एक मंत्री के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा उठाए जाने पर अदालत ने कहा कि इसे मुख्य याचिका के साथ टैग किया जाएगा और 9 दिसंबर को सभी संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई होगी।

इस दौरान आर्थिक बहिष्कार की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। पाशा ने कहा कि कई बाजारों में अल्पसंख्यक व्यापारियों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ बहिष्कार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रवृत्तियां देश की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इस समय केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने कहा कि दिशानिर्देश पहले से मौजूद हैं और उनका पालन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि हेट स्पीच का बढ़ता खतरा गंभीर है, लेकिन इसके समाधान के लिए वैधानिक ढांचा उपलब्ध है। अदालत ने संकेत दिया कि न्यायपालिका हर क्षेत्र में तत्काल हस्तक्षेप नहीं कर सकती और स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकारों को अपने हिस्से के दायित्व निभाने होंगे। अदालत ने राज्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से चेताया कि यदि दिशानिर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो भविष्य में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

चुनावी निष्पक्षता पर उठे सवाल: विपक्ष ने 'पक्षपाती' पुलिस अफसरों को हटाने की मांग तेज की

(जीएनएस)। कोलकाता का राजनीतिक माहौल विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर गर्म हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक विस्तृत पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि राज्य के कुछ पुलिस अधिकारी खुले तौर पर राजनीतिक झुकाव दिखा रहे हैं, जिससे आगामी चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है। अधिकारी ने दावा किया कि हाल ही में समुद्री पर्यटन नगरी दिघा में आयोजित पुलिस संघ के एक सम्मेलन में कुछ पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दोबारा सत्ता में आने की कामना करते हुए बयान दिए। यह टिप्पणी न केवल आचार संहिता की भावना के खिलाफ है, बल्कि यह पुलिस बल की तटस्थता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस में एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है, इसलिए विवादित अधिकारियों को चुनाव संबंधी किसी भी जिम्मेदारी से तत्काल हटाना अनिवार्य है ताकि मतदाताओं का विश्वास टूटने न पाए। इसके साथ ही अधिकारी ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती पर भी गहरी शंका व्यक्त की। उनका कहना है कि वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से की जा रही यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें तृणमूल कांग्रेस से जुड़े आई-पैक कर्मियों को शामिल किए जाने की संभावना है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी कार्य अत्यंत संवेदनशील होते हैं और उनमें संविदा कर्मचारियों की भागीदारी से डेटा की गोपनीयता और निष्पक्षता दोनों ही जोखिम में पड़ सकती हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पहले ही जिलाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि चुनावी कामों में संविदा कर्मियों के उपयोग से यथासंभव बचा जाए, ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर संदेह और गहरा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि चुनाव के मद्देनज़र स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही तैनात किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न बचे।

इस राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि 1,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर की नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे विवाद का विषय बनाना अनुचित है। ममता बनर्जी का यह भी तर्क है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, न कि राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर अनावश्यक सवाल खड़े करना। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहा है और चुनाव से पहले प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

राज्य की राजनीति में इन आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर ऐसे समय में तेज हुआ है जब चुनावी तैयारियाँ अपने चरम पर हैं और मतदाताओं के मन में पारदर्शिता को लेकर सवाल स्वाभाविक रूप से उभर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी की मांगों और ममता बनर्जी की आपत्तियों का यह टकराव चुनाव के करीब आते-आते और तीखा हो सकता है। चुनाव आयोग पर अब दबाव है कि वह इन दावों की निष्पक्ष जांच करे और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि पुलिस बल और प्रशासन के सभी स्तरों पर राजनीतिक तटस्थता बनी रहे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव हमेशा से ही तीखे टकराव, उच्चस्तरीय आरोपों और आक्रामक बयानबाज़ी के लिए जाने जाते रहे हैं, और इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे।

संपादकीय

पाक ड्रग-माफियाओं से बचाएं पंजाब के बच्चों को

नापाक पाक की ओर से सीमावर्ती राज्य पंजाब को अस्थिर करने की साजिश पिछली सदी से लगातार की जा रही है। लेकिन अब नशे का नश्तर सुनियोजित ढंग से इसके सीने पर जिस ढंग से चलाया जा रहा है, वह परेशान करने वाला है। पंजाब के पाक सीमा से लगे जिलों में नशीले पदार्थों की आपूर्ति लगातार जारी है। लेकिन अब इस साजिश में एक विचलित करने वाला अनैतिक मोड़ देखने को मिल रहा है। इसमें पाक स्थित ड्रग माफिया भारतीय सीमा में नाबालिगों को एक नशा आपूर्तिकर्ता के तौर पर भर्ती कर रहे हैं। यह कोई मामूली साजिश नहीं है, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तकनीकी बदलावों, कानून की खामियों और सबसे बढ़कर बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने का कुत्सित प्रयास ही है। दरअसल, सीमा पार बैठे नशा माफिया कानून के छिद्रों व परिस्थितियों का लाभ उठाने से नहीं चूकते। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का के किशोरों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इन किशोरों में कई आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों से हैं। जिन्हें चंद रुपयों का प्रलोभन दिया जाता है। उन्हें स्मार्टफोनों का लालच भी दिया जाता है। इसके अलावा जो किशोर नशे की दलदल में धंस चुके हैं उनकी कमजोर नस को पकड़कर उन्हें मुफ्त ड्रग्स का लालच दिया जाता है। किसी भी देश के किशोरों का नशे के संजाल में फंसना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे भविष्य के भारत के कर्णधार होते हैं। यदि वे अभी से नशे की दलदल और नशीले पदार्थों की आपूर्ति में लग जाएंगे तो देश-समाज का भविष्य कैसा होगा, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। जिस काम को किशोर लालच से अंजाम दे रहे हैं, सही मायनों में वह बेहद खतरनाक है। वे ड्रोन से गिराए गए हेरोइन के पैकेट व कुछ मामलों में खतरनाक अवैध हथियार उठाते हैं और उन्हें ड्रग माफिया द्वारा बताए गए एजेंटों तक पहुंचाते हैं।

दरअसल, आमतौर पर किशोरों की सामान्य सक्रियता को संदिग्ध नहीं माना जाता। उनका साफ-सुथरा रिकॉर्ड उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नजर से बचा लेता है। यदि नाबालिगों की गिरफ्तारी होती भी है तो वे भारतीय कानूनों के हिसाब से गंभीर सजा से बच जाते हैं। इस तरह, उनकी कम उम्र ही उन्हें सीमा पार बैठे नशे के तस्करों के लिये उपयोगी बना देती है। इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करते समय प्रवर्तन एजेंसियों को उदार रवैया अपनाना चाहिए। दरअसल, कुछ बच्चे परिस्थितियों के मारे भी होते हैं। वे मूलतः अपराधी नहीं होते। कुछ शातिर अपराधी उनका इस्तेमाल करके इस अपराध की दलदल में धकेल देते हैं। सही मायनों में वे सीमा पार से रची गई साजिश और हमारी अपनी व्यवस्था की कमजोरियों के कुचक्र व उससे उपजी आपराधिक व्यवस्था में आसानी से फंस जाते हैं। असल में, भारतीय किशोर न्याय कानून का उद्देश्य नाबालिगों को सुधारना और सुरक्षा करना होता है। लेकिन इस कानून की मूल भावना का लाभ संगठित नेटवर्कों द्वारा अपने मंसूबों को अंजाम देने को उठाया जा रहा है। हम 21वीं सदी में नशे की तस्करी का मुकाबला बीसवीं सदी के उपायों से नहीं कर सकते हैं। कभी-कभार होने वाली गिरफ्तारियां, छिटपुट छापे और उदार चेतावनी अपर्याप्त कही जा सकती हैं। निश्चित रूप से अपराध की घातकता के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। सीमा की निगरानी व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाये जाने की सख्त आवश्यकता है। स्कूलों, पंचायतों, सामुदायिक नेताओं और नागरिक समाज को पहले ही चेतावनी प्रणालियां बनानी चाहिए, ताकि पहचान हो सके कि बच्चों की परवरिश किस ढंग से की जा सके। इस दिशा में अभिभावकों को भी जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे बच्चों के पथभ्रष्ट होने के खतरे के प्रति सचेत रहें। समुदायों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही जोखिम के दायरे में आ सकने वाले युवाओं को बेहतर शिक्षा, कार्य कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे किसी प्रलोभन में आकर गलत राह न चुने। निश्चित तौर पर नाबालिगों का यह दुरुपयोग पंजाब के सामाजिक ताने-बाने व भारत की सुरक्षा पर हमला है।

अर्बन नक्सल अब खुलकर सामने आने लगे, इंडिया गेट पर प्रदर्शन में जो हुआ उसने गहरी चिंता पैदा की

> इस पूरी घटना की घोर निंदा आवश्यक है— न केवल इसलिए कि हिंसा हुई, बल्कि इसलिए भी कि लोकतांत्रिक विरोध की पवित्रता भंग हुई। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को किसी भी प्रकार की अतिवादी राजनीति से मुक्त रखना होगा।

दिल्ली में रविवार को हुए प्रदूषण-विरोधी प्रदर्शनों का उद्देश्य जितना वैध था, उसकी परिणति उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण। राजधानी की हवा विषैली हो चुकी है, नागरिकों का आक्रोश स्वाभाविक है और सरकारों से कड़े कदमों की अपेक्षा भी पूरी तरह जायज। परन्तु जिस प्रकार यह प्रदर्शन हिंसक हुआ, मिर्च-स्प्रे का उपयोग किया गया, पुलिसकर्मियों को चोट पहुँचाई गई और सबसे गंभीर बात कि एक माओवादी कमांडर हिडमा के पोस्टर लहराए गए, वह न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि सजग लोकतांत्रिक नागरिकता की मूल भावना पर प्रहार भी है। प्रदूषण पर चिंता जताने का लोकतांत्रिक अधिकार और नक्सलवाद का प्रचार दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में एक-दूसरे से मिलाया नहीं जा सकता। हिडमा जैसा व्यक्ति, जो दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए घातक रहा, अनेक निर्दोष ग्रामीणों की मौत का कारण बना और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देता रहा, यदि उसके पोस्टर राजधानी की सड़कों पर लहराए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र का गंभीर उपहास है। चाहे यह किसी "छोटी टुकड़ी" का कृत्य रहा हो या किसी सुनियोजित समूह का, यह कृत्य किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

सबसे पहले निंदा उस हिंसा की होनी चाहिए जो प्रदर्शनकारियों ने अपनाई। मिर्च-स्प्रे का इस्तेमाल, बैरिकेड तोड़ना, सड़क अवरोध, एम्बुलेंस जैसे आपात वाहनों को रोकना, ये सब लोकतांत्रिक विरोध के दायरे में

आते ही नहीं। संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, पर यह स्वतंत्रता दूसरों की सुरक्षा और अधिकारों को चोट पहुँचाने की अनुमति नहीं देती। पुलिसकर्मी भी इंसान हैं, वह रोज़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन पर इस तरह हमला पूरी तरह निंदनीय है।

दूसरी ओर, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को केवल "अर्बन नक्सल" कथा तक सीमित कर राहत की साँस न ले। प्रदूषण वास्तव में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। दिल्ली-NCR की हवा ऐसी है कि सुबह की सैर अब स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि नुकसानदायक हो चुकी है। हर साल सरकारें समितियाँ बनाती हैं, घोषणाएँ करती हैं, परंतु जमीनी बदलाव नहीं दिखते। आम आदमी का गुस्सा इसलिए फूटता है क्योंकि उसे नीतिगत निष्क्रियता साफ दिखाई देती है।

और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गुस्से का अर्थ यह नहीं कि किसी भी चरमपंथी विचारधारा को मंच मिल जाए। एक लोकतंत्र में ग़लत नीतियों की आलोचना की जा सकती है, परंतु लोकतंत्र विरोधी हिंसक संगठनों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। यह विरोध की सीमा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को ही दूषित कर देता है।

घटना का तीसरा पहलू इससे भी चिंताजनक कि हर बार की तरह यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाज़ी की भेंट चढ़ गया। जरूरी बात यह है कि सभी दल मिलकर प्रदूषण जैसे गंभीर संकट पर कदम उठाएँ। NCR के राज्यों के बीच समन्वय, निर्माण-धूल नियंत्रण, पराली प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, ये सब आज ही करने की ज़रूरत है। जनता सड़क पर इसलिए उतरती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ संस्थानों तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन यदि जनता में से भी कुछ लोग लोकतांत्रिक ढाँचे को ध्वस्त करने वाले तत्वों की तरफ झुक जाएँ, तो यह समाज की सामूहिक विफलता है।

इसलिए, इस पूरी घटना की घोर निंदा आवश्यक है— न केवल इसलिए कि हिंसा हुई, बल्कि इसलिए भी कि लोकतांत्रिक विरोध की पवित्रता भंग हुई। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को किसी भी प्रकार की अतिवादी राजनीति से मुक्त रखना होगा। हिडमा जैसे चरमपंथियों के पोस्टर राजधानी की सड़कों पर स्वीकार्य नहीं हो सकते। यह हमारे लोकतंत्र की संवेदनशीलता पर आघात है और इससे सख़्ती से निपटना ही होगा। बहरहाल, सरकारों को प्रदूषण पर ठोस और त्वरित कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे प्रदर्शन भटक कर हिंसा और अतिवाद का रूप न लें। नागरिकों का आक्रोश तभी सही दिशा में जा सकता है, जब राज्य व्यवस्था उसे सुनने और समाधान देने को तैयार हो। परंतु लोकतंत्र में कोई भी लक्ष्य हिंसा, भय और चरमपंथ के सहारे नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह समान रूप से नागरिक, सरकार और समाज, सभी की साझा जिम्मेदारी है कि विरोध भी हो, पर सभ्य, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप।

प्रेरणा

अविचल भक्ति का दीप

आचार्य विनोबा भावे वर्धा जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। दोपहर ढल रही थी, आसमान हल्की धूप और बादलों के मिश्रण से बना एक शांत चित्र था। रेलगाड़ी की पटरियाँ एक लय में गूँजती जा रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं कोई अनसुना संगीत बजा रही हो। डिब्बे में बैठे लोग आपस में हल्की-फुल्की बातें कर रहे थे, कोई अख़बार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर भागते खेतों को निहार रहा था। विनोबा जी की आँखों में गहरी शांति थी, जैसे भीतर किसी गूढ़ ध्यान का प्रवाह चल रहा हो। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। भीड़ तेज़ी से चढ़ी-उतरी। उसी भीड़ के साथ एक वृद्ध फ़कीर भी डिब्बे में चढ़ आया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, पैबंद लगे हुए। बाल सफ़ेद, आँखें धूप से तपे रेगिस्तान जैसी गहरी, और चेहरे पर ऐसी मुस्कान, जो किसी साधक के पास भी आसानी से नहीं होती। वह धीरे-धीरे चलकर एक कोने में बैठ गया, अपना छोटा झोला रखा, और शांत होकर आँखें मूँद लीं।

कुछ ही क्षण बाद उसने बहुत धीमे स्वर में एक भजन गाना शुरू किया। आवाज़ में न कोई आडंबर, न कोई दिखावा—वह तो जैसे किसी पत्थर के भीतर छिपे सोते की तरह निकल रही थी। उसका स्वर इतना निर्मल था कि डिब्बे में बैठे सभी लोग धीरे-धीरे मौन होते गए। बच्चों के हाथों में पकड़े खिलौने रुक गए, बुजुर्गों की पलकों पर ध्यान उतर आया, और मनुष्य का मन—जो हर समय शोर ढूँढ़ता है—पहली बार शांत हो गया।

विनोबा भावे उस भजन में खो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मीरा के पदों की गूँज फिर से जीवित हो गई हो। जैसे किसी युग-पुरुष की आत्मा उस फ़कीर के गले से बोल

रही हो। उनकी आँखें चमक उठीं—यह भक्ति का रूप उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था।

डिब्बे में आगे की ओर बैठा एक धनाढ्य जमींदार फ़कीर का भजन सुन रहा था, पर उसका मन भाव में नहीं, हिसाब में लगा था। उसे लगा यह सब पैसे कमाने का तरीका है। उसने जेब से पाँच रुपये का नोट निकाला और आगे बढ़ते हुए घमंड भरे स्वर में कहा—

"अरे बाबा, यह लो पाँच रुपये। भजन छोड़कर कोई फिल्मी गाना गाओ। लोगों का मनोरंजन होगा। इन भजनों में क्या रखा है?"

फ़कीर ने अपनी आँखें खोलीं, मुस्कुराया—वह मुस्कान ऐसी थी जिसमें न किसी से प्रश्न था, न किसी से शिकायत। उसने धीमे स्वर में कहा—

"साहिब, मेरा नियम है मैं केवल परमात्मा की स्तुति करता हूँ। मेरी वाणी उसी की है। मैं किसी इंसान की प्रशंसा के गीत नहीं गाता।"

जमींदार को यह बात खटक गई। वह हँसा—एक कठोर, अभिमानी हँसी, जिसमें तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। उसने और भी बड़ी रक़म निकाली—इस बार सौ रुपये का नोट—और फ़कीर के हाथ में जबरदस्ती थमाने की कोशिश करते हुए बोला—

"अरे बाबा, सौ रुपये कोई कम नहीं होते। नियम-वियम छोड़ो। सौ रुपये लो और एक फिल्मी गीत गाओ। ज़रा लोगों को भी मज़ा आए।"

फ़कीर ने सिर हिलाया। उसके स्वर में वही अडिग शांति थी—

"साहिब, सौ क्या चाहे आप एक लाख रुपये दे दें, मेरे प्रभु के भजन नहीं रुकेंगे। मेरा गीत बिकाऊ नहीं। यह दिल की आराधना है—बाजार का सामान नहीं।"

जमींदार के चेहरे पर पसीना आया। यात्रियों ने साँस रोक ली। शायद पहली बार किसी ने इतनी गरीबी में भी इतना साहस दिखाया था। फ़कीर की साधारण आवाज़ उस समय किसी राजा के आदेश से भी अधिक दृढ़ लग रही थी।

विनोबा भावे अपनी जगह से उठे। उनका हृदय श्रद्धा से भर उठा था। वह धीमे कदमों से फ़कीर के पास गए और उसे गले से लगा लिया। उनकी आँखें भर आईं। उन्होंने कहा—

"आज मैंने देख लिया कि सूर, तुलसी और मीरा की परंपरा अभी भी जीवित है। धन का लालच जिसके कदम न डिगा सके—वही सच्चा भक्त है। तुमने आज हमें भक्ति का सच्चा स्वरूप दिखा दिया।"

फ़कीर ने सिर्फ मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया, जैसे उसे श्रेय की कोई आवश्यकता ही न हो। वह फिर आँखें बंद कर भजन गाने लगा—और डिब्बा एक मंदिर में बदल गया। बिना घंटियों के, बिना दीपक के, बिना धूपबत्ती के—सिर्फ भक्ति की पवित्र खुशबू फैलती हुई। ट्रेन अपनी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन डिब्बे में बैठे सभी लोगों के भीतर कुछ रुक गया था—एक अनुभव, एक प्रकाश, एक सत्य।

कभी-कभी कोई साधारण-सा बूढ़ा फ़कीर हमें बता देता है कि ईश्वर को खोजने के लिए पर्वतों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बस दिल में वह लौ जलानी होती है जो किसी कीमत पर न बुझे।

सदैव प्रेरित करेगा गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान

भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में यदि किसी व्यक्तित्व की उपस्थिति सदियों से अडिग, उज्ज्वल और अमर रही है, तो वे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानवता के सच्चे रक्षक, अत्याचार के विरुद्ध अदम्य साहस के प्रतीक और धार्मिक स्वतंत्रता के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनका बलिदान केवल एक समुदाय या क्षेत्र के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। ऐसा बलिदान, जिसने भारत की आध्यात्मिक आत्मा को सुरक्षित रखा और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत को जीवंत किया।

श्री गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम त्यागमल था। वे छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब व माता नानकी जी की संतान थे। इनका जन्म 1 अप्रैल, 1621 ई. को अमृतसर में हुआ। प्रचलित धारणा है कि जब भी मानवता पर घोर अत्याचार होता है, तब मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए, किसी महापुरुष का आगमन होता है। गुरु जी के जन्म के समय, हिन्दुस्तान पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था जिसका मंसूबा पूरे भारत का इस्लामीकरण करना था।

धर्म परिवर्तन के लिए औरंगजेब द्वारा जारी अत्याचार से सताए हुए तत्कालीन हिंदू नेता पंडित कृपा राम जी कश्मीर से अपने साथियों के साथ आनंदपुर साहिब (पंजाब) में गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु जी से औरंगजेब के जुल्म को रोकने तथा धर्म की रक्षा करने की विनती की।

गुरु जी ने उनकी फरियाद सुनकर कहा कि ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए, किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। उस समय बालक गोबिंद राय ने पूरी वार्ता सुनकर अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि, आप जी से बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। इसलिए बलिदान आपको ही देना चाहिए। यह सुनकर, गुरु जी ने फरियादियों से कहा कि जाओ, औरंगज़ेब को कह दो, कि यदि गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तो पूरा भारत इस्लाम कबूल कर लेगा। यह संदेश जब औरंगज़ेब को मिला तो उसने गुरु जी को दिल्ली दरबार में उपस्थित होकर इस्लाम कबूल करने को कहा। तब गुरु जी ने दृढ़तापूर्वक फ़तवा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अपनी अवज्ञा का परिणाम मृत्यु के रूप में कबूलने के लिए कहा। सज़ा की तारीख 11 नवंबर, 1675 तय करके चांदनी चौक, दिल्ली में गुरु जी के साथ गए तीन श्रद्धालुओं - भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मती दास जी को क्रमशः देग में उबाला, जलाया और आरे से चीरकर शहीद कर दिया। इसके बाद भी जब गुरु तेग बहादुर घबराए नहीं, बल्कि दृढ़ रहे, तब गुरु जी का शीश भी धड़ से अलग कर दिया। भाई जैता जी वहां से उनका शीश लेकर पंजाब के लिए चल दिये। भाई जैता जी को दिल्ली से आते हुए, गांव गढ़ी कुशाला (बढ खालसा) सोनीपत में, शीश सहित मुगल फौज ने घेर लिया। इस गांव के, गुरु घर के सेवक भाई कुशाल सिंह दहिया ने अपने शीश को पुत्र के जरिये फौज के हवाले कर दिया और फिर भाई जैता जी फौज को चकमा दे कर, शीश सहित तरावड़ी, अम्बाला से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे। उनके शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने के लिए भाई जैता जी ने सेवा निभाई। पवित्र शरीर का दाह संस्कार लक्खी शाह वंजारा, जो उस समय व शिव के अमीर लोगों में शामिल थे, ने अपने गांव रायसिना (दिल्ली) में अपने घर में रखकर किया था।

गर्व की बात है कि हमारा हिंदुस्तान गुरुओं, संतों, महापुरुषों, फकीरों का देश है। यहीं हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र की धरती पर अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ एवं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हरियाणा सरकार की ओर से संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत श्री गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिन्द सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, धन्ना भगत, संत कबीर और संत रविदास आदि संतों व महापुरुषों के जीवन-चिंतन प्रचार-प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। हरियाणा के लोगों में गुरु तेग बहादुर के प्रति श्रद्धा ही है कि यहां उनकी याद में करीब 28 गुरुद्वारा साहिब हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत समागम ज्योतिसर (कुरुक्षेत्र) में मनाने का फैसला लिया। गुरु तेग बहादुर जी के इस 350वें शहीदी दिवस के समागम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 नवंबर, 2025 को भागीदारी होगी। पूरे प्रदेश में चार शोभा यात्राओं में गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में लाखों की संख्या में संगत कुरुक्षेत्र पहुंची है। पहली नवम्बर से 25 नवम्बर, 2025 तक हरियाणा में गुरु साहिब की स्मृति में अनेक आयोजन किए हैं जोकि जन-सहभागिता और आध्यात्मिक एकता की अनोखी मिसाल बने हैं। राज्यभर में से श्रद्धा यात्राएं निकाली गई हैं । प्रदेश के गांव-गांव में कीर्तन, भजन, सत्संग और गुरु साहिब जी की बाणी का पाठ किया गया। हरियाणा में सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विवि में 'गुरु तेग बहादुर चेयर' की स्थापना व अंबाला के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। टोहाना-जींद-नरवाना मार्ग को गुरु तेग बहादुर मार्ग नाम दिया जा रहा है। कलेसर क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर वन विकसित किया जा रहा है। यमुनानगर के किशनपुरा में जी.टी.बी. कृषि महाविद्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है। इनका मकसद गुरु तेग बहादुर के त्याग, बलिदान और मानवता के संदेश को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है।

गुरु साहिब जी के संदेश आज भी हमारे दिलों में उतने ही प्रभावशाली हैं, जितने 350 वर्ष पहले थे। उनकी अमर वाणी और अद्वितीय बलिदान हमें तथा आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। गुरु जी की शहादत संबंधी, गुरु परंपरा के समकालीन कवि 'सेनापति' ने अति सुंदर कहा है—

'प्रगट भयो गुरु तेग बहादर, सकल सृष्ट पै ढापी चादर'।

अभियान

शीतकाल की देवधारा में बहता एक दिव्य तीर्थ–यात्रा अनुभव

उत्तराखंड की ऊँची चोटियाँ जब सर्द हवाओं के साथ हिम की चादर ओढ़ने लगती हैं, तब चार धामों के कपाट बंद होने की परंपराएँ उस शांत पर्वतप्रदेश में एक अदृश्य आध्यात्मिक प्रकाश जगाती हैं। बदरीनाथ के पवित्र धाम में यह प्रक्रिया किसी यांत्रिक प्रशासनिक चरण की तरह नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से चली आती एक ऐसी जीवित साधना है, जिसमें देवत्व, प्रकृति और परंपरा तीनों मिलकर पर्वतों के भीतर एक नई ऋतु का द्वार खोलते हैं।

विजयादशमी के पावन दिन जब बदरीनाथ मंदिर परिसर में पंचांग खोला जाता है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, वेदपाठियों की गूंज फैलती है और धर्माधिकारी कपाट बंद की तिथि घोषित करते हैं—तब ऐसा लगता है मानो स्वयं नारायण ने हिमालय के शिखरों से वर्ष का अंतिम संदेश भेजा हो। इस वर्ष कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं, परंतु उससे पहले चलने वाली पंच–पूजा 21 नवंबर से आरंभ होकर पाँच दिनों तक देवभूमि को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है।

मार्गशीर्ष मास में बदरी विशाल के नर–रावल द्वारा दो विशेष पूजाएँ आवश्यक मानी गई हैं। माना जाता है कि यह पूजा स्वयं नारायण को शीतकाल के लिए

ध्यानावस्था में प्रवेश दिलाती है। पाँच दिनों की पारंपरिक बंद प्रक्रिया किसी साधारण क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य क्रम है, जिसमें प्रतिदिन एक मंदिर, एक परंपरा, एक मंत्र धीरे–धीरे मौन की ओर यात्रा करती है। सबसे पहले गणेश मंदिर के कपाट बंद होते हैं, फिर आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य मंदिर। तीसरे दिन वेद ऋचाओं का पाठ विराम लेता है—यह ऐसा क्षण होता है जैसे हिमालय स्वयं सुनकर शांत हो जाए। चौथे दिन लक्ष्मीजी की पूजा और कड़ाई भोग उन्हें अर्पित किए जाते हैं। और फिर आता है पाँचवाँ दिन—भाव और विरह से भरा हुआ, जब पूरे बदरीनाथ परिसर में एक ऐसी अनुभूति होती है मानो स्वयं देवता विदाई ले रहे हों। इसी दिन रावल स्त्री वेश धारण करते हैं। यह दृश्य देखने वाले लोग साक्षी बनते हैं एक ऐसी परंपरा के, जिसमें पुरुषत्व का अहंकार नहीं, बस श्रद्धा की विनम्रता होती है। रावल देवी पार्वती का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के चल–विग्रह को गर्भगृह में विराजमान करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि कोई पुरुष स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता। रावल का यह स्त्री–रूप धारण करना त्याग और श्रद्धा का ऐसा उदाहरण है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।

इसके बाद नारायण के चरणों में मौन उतर जाता है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देवभूमि की ठंडी हवा उस क्षण जैसे विघटित हो उठती है—जैसे कोई भावुक विदाई पर्वतों की घाटियों में गूंजकर लौट रही हो।

माणा गाँव की कुंवारी कन्याएँ इस अवसर पर एक घृत–कंबल तैयार करती हैं—देवता को शीतकाल में ऊष्मा देने के लिए। इसे बदरी गाय के घी में डुबोकर भगवान को ओढ़ाया जाता है। जब वसंत लौटता है और कपाट खुलते हैं, तो यही कंबल भक्तों में प्रसाद रूप में वितरित होता है—मानो वह भगवान की गर्म सांस लेकर लौट आया हो।

बदरीनाथ की अनोखी तुलसी की सुगंध इस पूरी प्रक्रिया को और भी दिव्य बनाती है। यहाँ किसी अन्य पुष्प का स्थान नहीं—केवल इस भूभाग में पाई जाने वाली दुर्लभ तुलसी से ही भगवान का श्रृंगार होता है। ऐसा मानो बदरी विशाल स्वयं इन पहाड़ों की आत्मा को अपने चरणों में धारण करते हों।

कपाट बंद होने के अगले दिन देव विग्रहों की एक यात्रा आरंभ होती है—कुबेर की डोली बामणी तक जाती है, उद्धव व शंकराचार्य की गद्दी पाण्डुकेश्वर के योगध्यान मंदिर तक। गरुड़ और मंदिर का खजाना भी नृसिंह मंदिर में लाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे देवता स्वयं अपने शीतकालीन घरों तक पहुँच रहे हों—दर्शन बंद नहीं होते, स्थान बदलता है, पर आस्था की लौ जलती रहती है।

गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ से भी देवी–देवताओं की चल–विग्रह मूर्तियाँ अपने शीतकालीन स्थलों की ओर प्रस्थान करती हैं। भले ही ऊँचे शिखरों पर कपाट बंद हो जाएँ, पर नीचे घाटियों में पूजा–अर्चना निरंतर चलती रहती है। यह केवल धूप और दीपक की परंपरा नहीं—यह सृष्टि के वामाव्रत क्रम की अनुभूति है। यमुना से भक्ति, गंगा से ज्ञान, केदारनाथ से वैराग्य और बदरीनाथ से मोक्ष—यह चारों का चक्र एक ब्रह्म–नाद की तरह अटूट है।

शीतकाल में यमुनोत्री की पूज्या यमुना माता खरसाली के खुशीमठ में विराजती हैं। गंगा माता मुखीमठ में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। केदारनाथ के पंचमुखी महादेव ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में निवास करते हैं। और बदरी विशाल की तेजस्वी धारा पाण्डुकेश्वर में उद्धव और कुबेर के साथ बहती रहती है।

इस यात्रा का सार यही है—देवता कहीं जाते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं। हमारी आस्था उनकी मौन यात्रा का अनुसरण करती है। पर्वतों की गोद में, हिम की शीतल चादर में, और घाटियों में जलती अखंड ज्योतियों में देवत्व हर ऋतु में जीवित रहता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर मोदी सरकार की कड़ी कार्रवाई, सात राज्यों पर 129 करोड़ से अधिक की वसूली शुरु

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश भर में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में सामने आई गड़बड़ियों ने केंद्र सरकार को कठोर रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मिशन की प्रगति की समीक्षा के दौरान खामियों को लेकर जताई गई सख्त नाराज़गी के बाद केंद्र सरकार ने सात राज्यों पर कार्रवाई करते हुए कुल 129.27 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई ने राज्यों की जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को लेकर केंद्र के रुख को और भी कठोर और स्पष्ट कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, गड़बड़ियों का सबसे बड़ा बोझ गुजरात पर पड़ा है, जहां से 120.65 करोड़ रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई है। इनमें से 6.65 करोड़ रुपये की राशि पहले ही राज्य सरकार द्वारा जमा करा दी गई है जबकि शेष राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसी तरह अन्य राज्यों में तमिलनाडु से तीन लाख रुपये, त्रिपुरा से 1.22 करोड़, असम से 5.08 लाख, महाराष्ट्र से 2.02 करोड़, कर्नाटक से 1.01 करोड़ और राजस्थान से 5.34 करोड़ रुपये की वसूली निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर आरोपित राशि 129.27 करोड़ रुपये में से 12.95 करोड़ रुपये की वसूली पूरी हो चुकी है और शेष राशि की रिकवरी के लिए केंद्र की ओर से समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्र के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा है कि जल जीवन मिशन जैसी जनकल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार, अनियमितता या गुणवत्ता से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मिशन से संबंधित शिकायतें चाहे किसी भी राज्य से हों, उनका जमीनी सत्यापन अनिवार्य रूप से हो और जहां भी दोष मिले, वहां बिना किसी अपवाद के दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी सख्त रुख के बाद विभिन्न राज्यों में हुए कार्यों का माइक्रो-लेवल से क्रॉस-वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें पाइपलाइन सप्लाई, सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण कार्यों के मानक, पेयजल कनेक्शन के वास्तविक क्रियान्वयन और वित्तीय लेनदेन में कई तरह के उल्लंघन पाए गए। गांवों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया यह मिशन अब तक करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुका है, लेकिन हाल में सामने आई अनियमितताओं ने सरकार को पूरी प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता की दिशा में नए सिरे से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद मंत्रालय ने राज्यों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या मानक उल्लंघन पाए जाने पर न केवल वसूली की जाएगी, बल्कि संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को आम जनता के बीच हुए उन मामलों के बाद बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिनमें बिना काम किए भुगतान, घटिया पाइपों का इस्तेमाल, फर्जी कनेक्शन दिखाना और निर्धारित मानकों से घटिया निर्माण की शिकायतें शामिल थीं।

विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र की यह कार्रवाई न केवल मिशन की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश भर में चल रहे अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए भी एक मजबूत संदेश है कि अनियमितताओं को अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि मॉनिटरिंग व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा तथा भविष्य में जल जीवन मिशन के हर चरण को तकनीक आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

केंद्र सरकार के रुख और उठाए गए गंभीर कदमों से स्पष्ट है कि जल जीवन मिशन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अब किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। देशभर के गांवों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में यह कठोर कार्रवाई एक बड़े सुधार की नींव मानी जा रही है, जो आने वाले समय में मिशन की गति और गुणवत्ता को और मजबूत करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि जनता के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप में हर घर तक पहुंचे।

महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत

पश्चिम रेलवे की सोनाली शिंगटे द्वारा शानदार प्रदर्शन

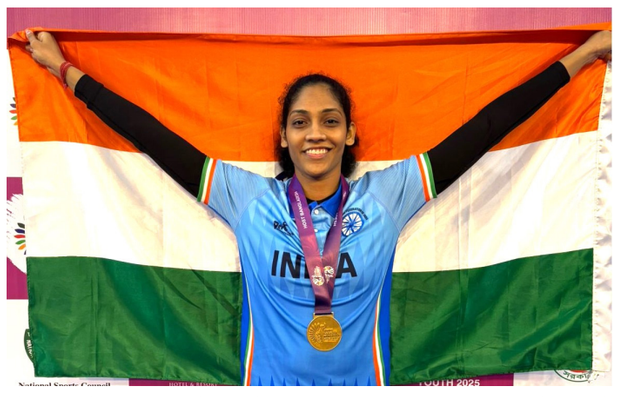

(जीएनएस)। भारत ने 17 से 24 नवंबर 2025 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी विश्व कप में रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह असाधारण उपलब्धि न केवल पूरे देश के लिए, बल्कि पश्चिम रेलवे के लिए भी अत्यंत गर्व का क्षण है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह पश्चिम रेलवे के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुंबई सेंट्रल मंडल में डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर (Dy CTI) के तौर पर काम करने वाली सुश्री सोनाली शिंगटे ने इंडियन टीम की राइट रेडर के तौर पर शानदार परफॉर्मेंस दी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपनी रेड्स में ज़बरदस्त फुर्ती, कॉन्फिडेंस और सटीकता दिखाई, जिससे भारत की जीत में अहम योगदान मिला। पश्चिम रेलवे को सुश्री सोनाली शिंगटे के डेडिकेशन और अचीवमेंट पर बहुत गर्व है। उनका योगदान न केवल इंडियन महिला कबड्डी टीम के लिए प्रतिष्ठा की बात है, बल्कि पूरे पश्चिम रेलवे परिवार के लिए भी बहुत सम्मान की बात है। पश्चिम रेलवे भारतीय महिला कबड्डी टीम को दिल से बधाई देती है और सुश्री सोनाली शिंगटे को उनके इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस के लिए सलाम करती है, जो रेलवे एथलीट्स के साथ-साथ देश भर के युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करता है।

अयोध्या में धर्मध्वजा फहराकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान—'गुलामी की मानसिकता त्यागें, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर करें गर्व'

(जीएनएस)। अयोध्या। रामनगरी की पवित्र वायु सोमवार को उस क्षण की साक्षी बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वजा फहराई और अयोध्या का आकाश गूंज उठा—'जय श्री राम' के दिव्य उद्घोष से। वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि, सूर्य की स्वर्णिमा रोशनी और हजारों श्रद्धालुओं की भावनाओं के बीच सम्पन्न इस अनुष्ठान ने इतिहास में एक और पवित्र अध्याय जोड़ दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संत-धर्माचार्य और देश-विदेश से आए श्रद्धालु उपस्थित थे, जिनकी आँखों में गर्व और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था।

शुभ मुहूर्त में बटन दबाते ही धर्मध्वजा आकाश की ओर उठने लगी, और जैसे-जैसे उसका केसरिया वस्त्र हवा में लहराया, प्रधानमंत्री की आँखों में भावनाओं की चमक तैर गई। यह केवल ध्वज का आरोहण नहीं था, बल्कि सनातन अस्मिता, संस्कृति और आस्था के दीप का प्रज्ज्वलन था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया और कहा कि यह क्षण केवल अयोध्या का नहीं, विश्व के हर उस हृदय का है जिसमें राम रमे हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रभु श्रीराम सदैव समानता, न्याय, सेवा और समभाव के आदर्शों पर चलते हैं। वे न किसी व्यक्ति के कुल को देखते हैं, न जाति को, न जन्म को—बल्कि व्यक्ति के भाव, कर्म और चरित्र को महत्व देते हैं। यही कारण है कि राम वनवासी निषादराज को गले लगाते हैं, शबरी के जूठे बेर को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं और निर्बल, वंचित, पीड़ित की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इसी भावना के साथ हर वर्ग के लिए समान रूप से विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़े—सभी को विकास की धारा में समान अवसर मिला है, और यही रामराज्य के आदर्शों का वास्तविक रूप है।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने उस मानसिकता पर भी गहरी चोट की, जो सदियों की गुलामी ने भारतीय मन में बो दी थी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब हमारी ही सांस्कृतिक धरोहर को कमतर आँका गया, हमारी ही परंपराओं का उपहास किया गया, और यहाँ तक कहा गया कि 'राम काल्पनिक हैं'। यह हमारी अपनी विरासत से दूर कर दिए जाने की साजिश का हिस्सा था। उन्होंने 1835 में मैकाले की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वही समय था जब मानसिक गुलामी के बीज बोए गए, और अब समय आ गया है कि देश का हर व्यक्ति मिलकर इस मानसिकता को त्यागने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 में मैकाले की नीतियों को लागू हुए 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और आने वाले दस वर्षों में हमें इस मानसिकता से पूर्ण मुक्ति का सामूहिक प्रयास करना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई भर नहीं है, बल्कि वह एक जीवंत सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों वर्षों में पनपी हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के प्राचीन शिलालेखों में आज से सैकड़ों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक निर्णयों के प्रमाण मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लेकिन गुलामी के दौर में हमारी पीढ़ियों से इस गौरवशाली इतिहास को छिपाया गया, ताकि भारतीय समाज अपनी ही धरोहर पर से विश्वास खो दे। उन्होंने इसे अब सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारतीय नौसेना के ध्वज में किए गए बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने ध्वज पर ऐसे प्रतीक अंकित थे जिनका भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं था। उन्हें हटाकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थान दिया गया है। यह केवल 'डिज़ाइन' नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की घोषणा है—दुनिया को यह बताने का क्षण कि भारत अपनी अस्मिता के साथ खड़ा है।

प्रधानमंत्री ने अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए कहा कि यही वह स्थान है जहाँ आदर्श व्यवहार का रूप लेते हैं। राम का युवराज से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का सफर निःस्वार्थ प्रेम, करुणा, ऋषि-गुरुओं के आशीर्वाद, निषादराज की मित्रता, मां शबरी के विश्वास और हनुमान की भक्ति से संपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इसी भावना को आज के भारत में जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपनी परंपराओं, अपनी ज्ञान-व्यवस्था और अपने गौरव को हृदय से अपनाएँ। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है।

राजकोट में आगामी 8 से 11 जनवरी, 2026 के दौरान आयोजित होगा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (वीजीआरई) – कच्छ तथा सौराष्ट्र

वीजीआरई 2026 कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में एमसएमई, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास को वेग देने के लिए सज्ज है

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात सरकार ने कच्छ तथा सौराष्ट्र अंचल के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के द्वितीय संस्करण की घोषणा की है, जो आगामी 8 से 9 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होगा। इस कॉन्फ्रेंस के साथ ही 8 से 9 जनवरी, 2026 के दौरान उसी स्थल पर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (वीजीआरई) भी आयोजित होगा; जो समग्र कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र के उद्योगों, एमएसएमई, सरकारी संस्थाओं एवं उद्यमियों के लिए एक उच्च प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिरामिक्स, इंजीनियरिंग, बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक्स, मत्स्योद्योग, पेट्रोरसायन, कृषि एवं खाद्य प्रंस्करण, खनिज सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक भागीदारी, पॉलिसी सपोर्ट तथा निवेशकों के सहयोग द्वारा गुजरात के पश्चिमी पट्टे में समाविष्ट विकास तथा टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के साथ औद्योगिक विकास को वेग देना है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर गुजरात में आयोजित प्रथम कॉन्फ्रेंस को असाधारण सफलता मिली थी; जिसमें 18000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को समाविष्ट किया गया था, छह थीमेटिक पैवेलियन बनाए गए थे, 170 से अधिक एमएसएमी सहित 410 से अधिक एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया था और इस कॉन्फ्रेंस में 80000 से अधिक मुलाकाती आए थे। आगामी समय में आयोजित होने वाली वीजीआरसी का उद्देश्य अधिक बड़ा एवं अधिक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करना है। कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस में 6 अत्याधुनिक डोम के साथ 20000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को समाविष्ट किया जाएगा; जिसमें क्षेत्रीय प्रदर्शनी, नवीनीकरण प्लेटफॉर्म तथा बिजनेस नेटवर्किंग अवसरों का समावेश होगा।

इस एग्जीबिशन में एग्रो, फूड प्रोसेसिंग एवं फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग, बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक्स, हथकरघा एवं हस्तकला, रसायन एवं पेट्रोरसायन, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ तथा शिक्षा संस्थाएँ सहित उच्च विकास क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियाँ और संस्थाएँ भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त; ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग, कृषि विभाग, गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, गुजरात खनिज विकास निगम, वन विभाग, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, शिक्षा विभाग, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन विभाग तथा स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स जैसे अनेक प्रमुख सरकारी विभाग और एजेंसियाँ भी इस एग्जीबिशन में भाग लेंगे।

क्राफ्ट विलेज तथा बड़ी संख्या में एमएसएमई की भागीदारी से इस क्षेत्र की समृद्ध कौशल परंपरा तथा उद्यमिता उजागर होंगे। वीजीआरई 2026 का मुख्य आकर्षण वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिवर्स बायर-सेलर मीट तथा उद्यमी मेला होंगे; जिसका उद्देश्य मार्केट में नए अवसर सृजित करना तथा स्थानीय एमएसएमई, कारीगरों व हथकरघा एवं हस्तकला व्यवसायों को वैश्विक खरीदारों के साथ जोड़ने में सहायता करना है। मुलाकातियों के अनुभव को समृद्ध बनाने एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए दैनिक लकी ड्रॉ भी आयोजित किया जाएगा।

अपेक्षा है कि कच्छ तथा सौराष्ट्र के शीर्षस्थ उद्योगपति, उद्यमी, कृषि-व्यवसाय विशेषज्ञ, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थाएँ, कारीगर तथा महिला उद्यमी इस प्रदर्शनी में सहभागी होंगे। उनकी उपस्थिति से वीजीआरई सहयोग, नवीनता तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनेगा। वीजीआरई राज्य में समावेशी विकास, निवेश को प्रोत्साहन देने, एमएसएमई को मजबूत बनाने और हर क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पश्चिम रेलवे मुख्यालय, मुंबई में अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारियों श्री विकाससिंह, प्वाइंट्समैन और श्री कमलेश कुमार एम., लोको पायलट को उत्कृष्ट कार्य एवं सुरक्षित ट्रेन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। इन दोनों कर्मचारियों को अक्टूबर 2025 के दौरान अपनी सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा से संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए सम्मानित किया गया। 03 अक्टूबर 2025 को सामाखियाली स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान प्वाइंट्समैन श्री विकाससिंह ने एक लॉन्ग हॉल ट्रेन के वैगन (CNCR 5452113254) के एक्सल पर दो बोल्ट गायब पाए। उन्होंने तुरंत लाल सिग्नल देकर ट्रेन को रोका। जांच में बोल्ट गायब होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद CCR के निर्देशानुसार वैगन को C&W स्टाफ द्वारा अटेंड करने हेतु ट्रेन को लाइन नंबर 03 पर लाया गया और सुरक्षित तरीके से आगे की कार्यवाही की गई। उनकी सजगता के कारण एक संभावित गंभीर तकनीकी त्रुटि समय रहते टल गई। 04 अक्टूबर 2025 को ट्रेन संख्या 69243 असारवा–उदयपुर को चलाते समय लोको पायलट श्री कमलेश कुमार एम. ने हिम्मतनगर से आगे किलोमीटर 321/12–321/11 पर तीन अज्ञात व्यक्तियों को रेलवे ट्रैक पर वस्तुएँ रखते देखा। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को अवरोध से लगभग 15 मीटर पहले सुरक्षित रूप से रोक लिया।

जांच में पाया गया कि ओएचई कैंटिलीवर असेंबली (रजिस्टर आर्म) का एक हिस्सा पटरियों पर गिरा हुआ था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी और लोहे की रॉड को सुरक्षित कर आगे की सभी प्रक्रियाएँ नियमों के अनुसार पूरी कीं। उनकी तत्परता और त्वरित निर्णय क्षमता ने एक बड़ी दुर्घटना को टालने में अहम भूमिका निभाई।

अहमदाबाद मंडल को अपने ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार कर्मचारियों पर गर्व है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्य, सतर्कता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हैं। यह सम्मान न केवल उनकी कर्तव्यपरायणता की सराहना है, बल्कि पश्चिम रेलवे की उस कार्य-संस्कृति का प्रतीक भी है, जहाँ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में 6वीं डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन (ADSA) द्वारा आयोजित 6वीं डीआरएम चैंपियनशिप का शुभारंभ 25 नवंबर 2025 को साबरमती स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया गया। इस आयोजन की शुरुआत एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा की गई। वर्ष 2025-26 की इस चैंपियनशिप में 10 खेल और कुल 38 इवेंट शामिल हैं। अहमदाबाद मंडल के 16 विभागों के लगभग 1100–1200 कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जो इसे पश्चिम रेलवे की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक बनाता है। प्रतिस्पर्धा में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज और एथलेटिक्स सहित कई लोकप्रिय खेल शामिल हैं। कुल 16 टीमें विभिन्न विभागों, कारखाने, साबरमती स्टोर तथा गांधीधाम एरिया मैनेजर टीम से भाग ले रही हैं। डीआरएम चैंपियनशिप का उद्देश्य खेल भावना को प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों में टीमवर्क बढ़ाना तथा शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। यह आयोजन कर्मचारियों को खेलों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

स्वदेशी ऊर्जा नवाचार को नई रफ्तार, हरदीप सिंह पुरी ने एचपीसीएल के हरित अनुसंधान केंद्र में देखा भविष्य का भारत

मुंबई और बेंगलुरु के बीच फैला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र इस समय जिस बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है, उसे बेंगलुरु स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हरित अनुसंधान एवं विकास केंद्र की प्रयोगशालाओं में साफ-साफ महसूस किया जा सकता है। जब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी यहां पहुंचे तो यह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं था; यह ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की उस यात्रा का वास्तविक दर्शन था, जिसमें विज्ञान, नवाचार और स्वदेशी तकनीक भविष्य की दिशा तय कर रही है।

एचपीसीएल के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्री का स्वागत किया और उन्हें उन प्रयोगशालाओं से रूबरू कराया जहाँ 150 से अधिक वैज्ञानिक दिन-रात काम कर रहे हैं, जिनमें 37% महिलाएँ हैं—जो ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में महिला नेतृत्व के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मंत्री ने इस योगदान की खुले शब्दों में सराहना की और इसे भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण वह क्षण था जब हरदीप सिंह पुरी ने हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन पायलट प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट सुनने में भले वैज्ञानिक शब्दों का संग्रह लगे, लेकिन असल में यह समुद्री शैवाल से बायो-क्रूड बनाने की क्रांतिकारी क्षमता रखता है। यानी समुद्र में उगने वाली साधारण-सी शैवाल ऊर्जा का भविष्य बन सकती है—और भारत इस तकनीक को अपनाने वाले शुरुआती देशों में से एक बनकर उभर रहा है। मंत्री ने इसे जैव-ऊर्जा क्षेत्र में "गेम चेंजर" बताते हुए कहा कि यह तकनीक भारत की स्वदेशी शोध क्षमता को मजबूत करने वाली उपलब्धि है।

इसके बाद केंद्र की इंजन प्रयोगशाला में वह प्रदर्शन किया गया जहां दोपहिया वाहनों के लिए फ्लेक्स-फ्यूल रेट्रोफिट किट दिखाई गई। भारत भविष्य में अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की दिशा में बढ़ रहा है, और यह तकनीक उसी दिशा में बढ़ाया गया दृढ़ कदम है। मंत्री ने इसे शहरी परिवहन और ग्रामीण आजीविका दोनों के लिए लाभकारी बताया।

यात्रा आगे बढ़ी तो मंत्री उन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में पहुंचे, जहां भविष्य की बैटरियां जन्म ले रही हैं—लिथियम-आयन, सोडियम-आयन और वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरियां। इन्हीं दीवारों के भीतर 1 kW लिथियम-आयन बैटरी पैक सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, जो आने वाले समय में भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई मजबूती देगा। एचपीजीआरडीसी ने अल्कलाइन और AEM इलेक्ट्रोलाइजर्स के स्वदेशी निर्माण में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 1 मेगावॉट समतुल्य शॉर्ट-स्टैक प्रमाणन प्राप्त किया है—जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन को कम लागत में उपलब्ध कराने की दिशा में असाधारण सफलता मानी जा रही है।

दौरे के अंत में मंत्री ने कहा कि यह केंद्र केवल शोध का संस्थान नहीं बल्कि देश की ऊर्जा कहानी का भविष्य है।

सुरेन्द्रनगर-चमारज सेक्शन में ब्लॉक के चलते रेल यातायात होगा प्रभावित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, राजकोट मंडल के सुरेन्द्रनगर-चमारज सेक्शन में नया रोड ओवर ब्रिज (आरओबी-48) बनाने के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस ब्लॉक के चलते 29 नवम्बर से लेकर 01 दिसम्बर, 2025 तक रेल यातायात प्रभावित होगा। भावनगर मंडल की प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

29 नवम्बर, 2025 को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

- ट्रेन नं 11466 जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस मार्ग में 02.00 घंटा रेगुलेट की जाएगी।
- ट्रेन नं 19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

30 नवम्बर, 2025 को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

- ट्रेन नं 19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस वेरावल से अपने निर्धारित समय 7.30 बजे की
- जगह 2 घंटा विलंब से यानि 09.30 बजे प्रस्थान करेगी।
- ट्रेन नं 19119 गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से अपने निर्धारित समय
- 10.25 बजे की जगह 2 घंटा विलंब से यानि 12.25 बजे प्रस्थान करेगी।

1 दिसम्बर, 2025 को प्रभावित होने वाली ट्रेनें:

- ट्रेन नं 11464 जबलपुर-वेरावल एक्सप्रेस मार्ग में 03.00 घंटा रेगुलेट की जाएगी।
- ट्रेन नं 19119 गांधीनगर कैपिटल-वेरावल एक्सप्रेस गांधीनगर कैपिटल से अपने निर्धारित समय
- 10.25 बजे की जगह 1 घंटा विलंब से यानि 11.25 बजे प्रस्थान करेगी।
- ट्रेन नं 19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस मार्ग में 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

अहमदाबाद के कारीगरों ने बुना आस्था का स्वर्ण धागा—अयोध्या राम मंदिर के लिए विशेष 'धर्म ध्वज' तैयार, परंपरा और विज्ञान का अद्भुत संगम

(जीएनएस)। अयोध्या और अहमदाबाद। अयोध्या में जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा, तब केवल रामनगरी ही नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद की गलियों में भी गर्व और भावनाओं की लहर दौड़ उठेगी। इसका कारण यह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस ऐतिहासिक क्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक—धर्म ध्वज—अहमदाबाद के कारीगरों ने अपने हाथों, अपनी निष्ठा और अपनी शिवभावना से तैयार किया है। यह ध्वज केवल कपड़ा नहीं, बल्कि परंपरा, विज्ञान, कला और श्रद्धा का ऐसा अद्भुत संगम है, जो भारत की सनातन आत्मा के गौरव को आसमान तक ले जाने वाला है।

22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और लगभग 2.5 किलोग्राम वजन वाला यह धर्म ध्वज आधुनिक तकनीक और प्राचीन वैदिक प्रतीकों का अनूठा मेल है। इसे नायलॉन-रेशम मिश्रित विशेष पॉलीमर कपड़े से तैयार किया गया है, जिसमें इतनी मजबूती है कि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं, भीषण गर्मी, भारी बारिश और मौसम के चरम उतार-चढ़ाव को भी सहज ही झेल सकता है। इससे पहले जो ध्वज भेजा गया था, उसका वजन 11 किलोग्राम था, जिसे बदलने के बाद इस नए ध्वज को हल्का, टिकाऊ और तकनीकी रूप से अधिक उपयुक्त बनाया गया है। यह ध्वज हर तीन वर्ष में बदला जाएगा, ताकि मंदिर के शिखर पर सदैव नवीन, प्राणवान और तेजस्वी ध्वज लहराता रहे। इस धर्म ध्वज की विशेषता केवल इसका आकार या मजबूती नहीं है, बल्कि वे वैदिक प्रतीक हैं जो इसे विशिष्ट आभामंडल प्रदान करते हैं। ध्वज का केसरिया रंग धर्म, त्याग, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र न्याय, गति और धर्म की सतत चलने वाली धारा को दर्शाता है। सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें तेजस्वी सूर्य का अंकन किया गया है, जो यह स्मरण कराता है कि श्रीराम केवल राजा नहीं, सूर्यवंशी आदर्श पुरुष हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पवित्र कोविदार वृक्ष भी ध्वज पर सुशोभित है, जो रामराज्य की शांति, समृद्धि और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही सर्वव्यापी सत्ता, सृजन और ऊर्जा के प्रतीक 'ॐ' का अंकन ध्वज को पूर्ण आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करता है। इन सभी प्रतीकों का संयोजन इस ध्वज को मात्र धार्मिक ध्वज नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के गहन दर्शन का जीवंत रुप बनाता है।

अहमदाबाद के कारीगरों ने महीनों की मेहनत, साधना और कौशल से इस ध्वज को तैयार किया। शहर की गलियों में रहने वाले साधारण मजदूरों और बुनकरों ने इसे केवल कार्य नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और धर्मसेवा मानकर बनाया। धागा-धागा जोड़ते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि उनका श्रम केवल एक ध्वज में नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज हो रहा है। उनके लिए यह काम रोटी-रोज़गार से अधिक आत्मिक संतोष का था, क्योंकि वे जानते थे कि यह ध्वज अयोध्या के शिखर पर फहराकर भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बन जाएगा। केवल धर्म ध्वज ही नहीं, राम मंदिर से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण भी गुजरात की भूमि पर ही हुआ है। अहमदाबाद के दबगर समुदाय ने मंदिर के प्रांगण में बजने वाला विशाल ढोल तैयार किया है। यह ढोल अपनी ध्वनि में अद्भुत गूंज रखता है और धार्मिक उत्सवों में वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह और आसपास बने छह अन्य मंदिरों के ध्वज-स्तंभ भी गुजरात में ही निर्माणित हुए हैं। मंदिर पर रखी पवित्र चूड़ियां, भगवान के आभूषणों के लिए पीतल की बनी अलमारी, दानपात्र और मंदिर के दरवाजों का श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला हार्डवेयर—ये सभी अहमदाबाद के कारीगरों के हाथों की कारीगरी हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शिल्प दोनों का सम्मिश्रण किया गया है।

जब धर्म ध्वज अयोध्या की पवित्र हवा में लहराएगा, तब उस लहर में अहमदाबाद के कारीगरों के हाथों का स्पर्श, उनकी भक्ति, उनकी कला और उनकी भावना भी शामिल होगी। यह ध्वज केवल राम मंदिर का अलंकार नहीं, बल्कि अखिल भारत की श्रम-श्रद्धा का अद्वितीय प्रतीक बनेगा। यह क्षण अयोध्या के लिए जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही अहमदाबाद के उन साधारण, मेहनतकश कारीगरों के लिए भी, जिनकी कला ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है।

भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के ऐतिहासिक मुकाम पर, अहमदाबाद बनेगा वैश्विक खेलों का नया द्वार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय खेलों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी vrijwel सुनिश्चित कर चुका है और अब अंतिम घोषणा का इंतज़ार है, जो ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में की जाएगी। यह वह क्षण है, जिसका इंतज़ार देश ने पिछले कई वर्षों से किया है। यदि सब कुछ अनुमान के अनुरूप रहा, तो भारत 2010 के दिल्ली गेम्स के दो दशक बाद एक बार फिर इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा और वैश्विक खेलों की दुनिया में एक बार फिर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।

इस बार आयोजन के केंद्र में होगा अहमदाबाद, जिसे भारत ने 2030 संस्करण के लिए मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया है। यह निर्णय किसी संयोग का परिणाम नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अहमदाबाद ने जिस तरह विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना खड़ी की है, उसने न केवल भारत की दावेदारी मजबूत की बल्कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड को भी यह विश्वास दिलाया कि यह शहर वैश्विक खेल आयोजन के सभी मानकों पर खरा उतर सकता है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक, शहर अपने विशाल एवं अत्याधुनिक ढाँचे के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहले से ही सुर्खियां बटोर चुका है।

भारतीय प्रस्ताव पर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स बोर्ड की मूल्यांकन समिति ने गंभीर और बहु-आयामी अध्ययन किया। इस अध्ययन में न केवल स्टेडियमों और उनके तकनीकी ढांचे की जाँच हुई, बल्कि खिलाड़ियों के निवास, परिवहन, आयोजकीय क्षमता, सुरक्षा प्रबंधन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय मानकों की भी समीक्षा शामिल थी। समिति ने पाया कि भारत ने अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा उपायों और पर्यावरणहितैषी योजनाओं के साथ एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत किया है। इससे भारत की मेजबानी दावेदारी और मजबूत हो गई।

हाल के महीनों में अहमदाबाद में खेल आयोजनों का जो सिलसिला दिखाई दिया, उसने भारत की विश्वसनीयता को और बढ़ाया। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियन कप 2026 क्वालिफायर ने इस शहर की मेजबानी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। आने वाले वर्ष में यहां एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और एशिया पैरा-आर्चरी कप का आयोजन भी प्रस्तावित है, जो इस दावेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा।

मेजबानी की इस दौड़ में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के अबुजा शहर से था, लेकिन कॉमनवेल्थ संगठन ने नाइजीरिया की मेजबानी क्षमता को देखते हुए उसे 2034 संस्करण के लिए विचार करने का फैसला किया है। इससे भारत की राह लगभग साफ हो चुकी है। संगठन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अफ्रीकी देशों की भागीदारी भी भविष्य में मजबूत बनी रहे, इसलिए अबुजा को दीर्घकालिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ग्लासगो में होने वाली असेंबली भारत के लिए निर्णायक साबित होगी। भारत की ओर से एक विस्तृत विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 2030 गेम्स के आयोजन मॉडल, पर्यावरण संरक्षण की रणनीतियाँ, स्थायी अवसंरचना, भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन और युवाओं को प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाएगा। यह विजन डॉक्यूमेंट इस बात का भी प्रमाण होगा कि भारत केवल खेल आयोजन की मेजबानी नहीं करना चाहता, बल्कि खेलों के माध्यम से एक नए वैश्विक नैरेटिव का निर्माण भी करना चाहता है। देशभर में उत्सुकता और उत्साह चरम पर है। खिलाड़ी, कोच, विश्लेषक, उद्योग जगत, पर्यटन से जुड़े लोग और आम नागरिक—सभी इस घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि भारत को आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलती है, तो यह न केवल भारतीय खेल जगत के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय साख और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। संभावना है कि भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे एक विशेष प्रसारण के माध्यम से दुनिया को 2030 के मेजबान के रूप में भारत का नाम सुनाई देगा। वह क्षण लाखों भारतीयों के लिए गर्व, उत्साह और नए सपनों का क्षण होगा—एक ऐसा क्षण, जो भारत के खेल इतिहास को नए भविष्य की ओर ले जाएगा।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 70 मीटर का विशाल स्टील ब्रिज स्थापित, परियोजना ने रफ्तार पकड़ी

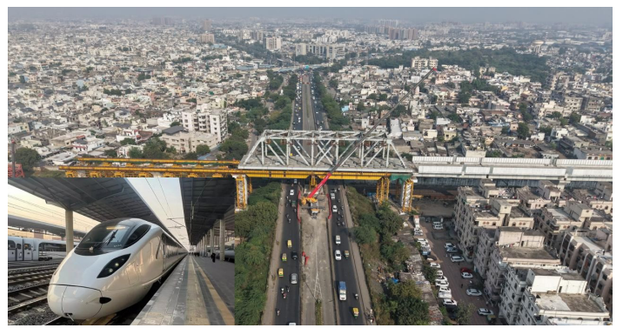

(जीएनएस)। ठाणे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुकी है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर 70 मीटर लंबा और 670 मीट्रिक टन वजनी स्टील ब्रिज लॉन्च किया गया, जिसने पूरी परियोजना को एक और ठोस दिशा दी है। अहमदाबाद जिले के कैडिला फ्लाईओवर पर स्थापित यह विशालकाय संरचना न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और तेज़ी से बढ़ती आधारभूत संरचना का जीवंत उदाहरण भी है।

यह ब्रिज कुल 13 मीटर ऊँचा और 14.1 मीटर चौड़ा है। इसे गुजरात के नवसारी स्थित अत्याधुनिक वर्कशॉप में तैयार किया गया जहां विशेषज्ञों की टीम ने महीनों की मेहनत से इस संरचना को रूप दिया। तैयार होने के बाद इसे भारी-भरकम हेवी-ड्यूटी ट्रेलर के माध्यम से सावधानीपूर्वक कैडिला साइट तक पहुँचाया गया। वहाँ इसके लिए विशेष रूप से 16.5 मीटर ऊँची स्टील स्टेजिंग तैयार की गई थी, जहां ब्रिज की असेंबली को उच्च सुरक्षा और सटीक तकनीकी मानकों के साथ पूरा किया गया।

इस स्टील ब्रिज का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार किया गया है। इसे जोड़ने के लिए लगभग 29,300 हाई स्ट्रेंथ TTHS बोल्ट का उपयोग किया गया, जिनकी मजबूती और टिकाऊपन इसे दशकों तक बिना किसी संरचनात्मक कमी के सहारा देने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, पूरे ब्रिज पर C-5 सिस्टम पेंटिंग की गई है, जो इसे मौसम, नमी और पर्यावरणीय क्षरण से दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेगी।

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए कुल 28 स्टील ब्रिज बनने हैं, जिनमें से 17 गुजरात में और 11 महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे। यह 11वां स्टील ब्रिज सफलतापूर्वक लॉन्च होने के साथ ही यह संकेत भी मिला है कि परियोजना निर्धारित गति से आगे बढ़ रही है और कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है।

भारत के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकी छलांग का प्रतीक है। इस कॉरिडोर पर 320 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन देश में हाई-स्पीड यात्रा का नया अध्याय खोलेगी। ऐसे में कैडिला फ्लाईओवर पर इस विशाल स्टील ब्रिज का सफलतापूर्वक स्थापित होना पूरे कॉरिडोर की प्रगति को गति देने वाला संकेत है।

इंजीनियरों की टीम, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों की सामूहिक मेहनत से बनी यह उपलब्धि न केवल परियोजना की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत अब विश्वस्तरीय हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और अपनाना दोनों में सक्षम है।

राजस्थान में मासूम की दर्दनाक मौत, 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरने के बाद ऊपर से डाली गई रोड़ी, परिजन गायब—गांव में सनसनी

(जीएनएस)। राजस्थान के खैरथल-तिजारा क्षेत्र के हसनपुर माफी गांव से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। महज चार साल की एक मासूम बच्ची की मौत क्रेशर मशीन संचालित स्थल पर हुई लापरवाही का भयावह परिणाम बनकर सामने आई। बच्ची खेलते-खेलते 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे भी दुखद यह कि उसी दौरान क्रेशर मशीन से गड्ढे में ऊपर से रोड़ी (पत्थरों का मलबा) डाली गई, जिससे बच्ची दब गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव में मौजूद क्रेशर पर यूपी के प्रयागराज निवासी अमित और उसकी पत्नी मजदूरी करते थे। रोज़ की तरह 20 नवंबर को भी दोनों पति-पत्नी काम कर रहे थे और उनकी दोनों बेटियां पास ही खेल रही थीं। खेलते-खेलते वे क्रेशर के पत्थर ढेर के पास चली गईं। अचानक बड़ी बेटी परी का पैर फिसल गया और वह सीधे 15 फीट नीचे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी।

उसी समय क्रेशर मशीन लगातार चल रही थी और मशीन ऑपरेटर द्वारा ऊपर से पूरे गड्ढे में एक डंपर रोड़ी डाल दी गई। किसी ने यह नहीं देखा कि गड्ढे में एक बच्ची गिरी हुई है। जब काफी देर तक परी दिखाई नहीं दी तो मां घबरा गई और उसे खोजने लगी। छोटी बहन ने गड्ढे की ओर इशारा किया, जिसके बाद मजदूरों ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर खुदाई कराई। काफी प्रयासों के बाद गड्ढे से निकाले गए मलबे में परी का निर्जीव शव मिला।

घटना के बाद हालात और भी संदिग्ध हो गए। सूत्रों के अनुसार, क्रेशर मालिक और बच्ची के माता-पिता अंतिम संस्कार करने जा रहे थे कि तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तिजारा उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी बीच गांव के विधायक महंत बाबा बालकनाथ का आरोप सामने आया कि क्रेशर मालिकों ने घटना को छुपाने के प्रयास में बच्ची के माता-पिता को यूपी भेजकर "गायब" कर दिया है। विधायक ने कहा कि उन्होंने 21 नवंबर को परी के माता-पिता से बात की थी और उन्हें 22 नवंबर को जनसुनवाई में बुलाया था, लेकिन वे न तो पहुंचे और न ही फ़ोन उठा रहे हैं। विधायक का आरोप और भी गंभीर है—उनके अनुसार, यह केवल दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या जैसी संगठित लापरवाही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि क्रेशर बंद होता, तो गड्ढा खुला क्यों था? उस गड्ढे में रोड़ी कैसे डाली गई?

विधायक ने आश्वासन दिया है कि मासूम को न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और क्रेशर संचालकों तथा जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

यह घटना प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मजदूर परिवारों की असुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गांव में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल बना हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले और क्रेशर संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों।

भारत से श्रीलंका तक रामायण की पावन भूमि का सफर—IRCTC ने लॉन्च किया 'श्रीलंका, द रामायण यात्रा' पैकेज, 2026 से धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

(जीएनएस)। भारत और श्रीलंका की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जोड़ने वाली रामायण यात्रा अब और अधिक सुलभ होने जा रही है। IRCTC ने नए वर्ष के अवसर पर जिस विशेष पैकेज की घोषणा की है—'श्रीलंका, द रामायण यात्रा'—वह केवल एक पर्यटन कार्यक्रम नहीं बल्कि रामायणकालीन स्थलों की वास्तविक अनुभूति का विरल अवसर है। सीमित सीटों वाला यह विशेष पैकेज 35 चयनित यात्रियों को उन सभी स्थानों तक ले जाएगा, जिन्होंने आदिकाल से रामायण कथा में स्वयं की उपस्थिति दर्ज कराई है। 2026 से रामायण सर्किट और श्रीलंका कनेक्टिविटी को और विस्तारित करने की तैयारी है, और यह पैकेज उसी दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है।

यह यात्रा जयपुर से शुरू होगी, जहां से यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलंबो पहुँचेंगे। हवाई यात्रा की सुविधा, आवास, भोजन, गाइड सेवा, प्रवेश टिकट, वीज़ा शुल्क और बीमा सहित सम्पूर्ण यात्रा 71,440 के पैकेज में उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रा की अवधि कुल 6 दिन और 5 रात होगी, जिसके अंतर्गत यात्रियों को उन सभी स्थलों पर ले जाया जाएगा जो भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पवित्र कथा से जुड़े हुए हैं।

कोलंबो पहुँचने के बाद यात्रियों का पहला पड़ाव होगा सीता अम्मन मंदिर, जहाँ पुराणों के अनुसार माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इसके बाद अशोक वाटिका—हक्गला गार्डन—दर्शन कराए जाएंगे, जिसे वह स्थान माना जाता है जहाँ राक्षसराज रावण ने सीता माता को रखा था। यात्रा में रावण गुफा भी शामिल है, जिसे परंपरा के अनुसार रावण का आवास माना जाता है। कोलंबो स्थित विभीषण मंदिर, जो भगवान राम के अनन्य भक्त और लंका के धर्मात्मा राजा विभीषण को समर्पित है, भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

भव्य रामबोडा हनुमान मंदिर, जहाँ मान्यता है कि हनुमान जी लंका दहन से पहले उतरे थे, भी यात्रा की पवित्र श्रृंखला का हिस्सा रहेगा। इसके अतिरिक्त मुन्नेश्वरम मंदिर, मनावरी मंदिर—जिसे रामेश्वरम के पूरक का दर्जा प्राप्त है—गायत्री पेडम और दिवुरुम्पोला मंदिर जैसे कई शक्तिपीठ यात्रियों को रामायण की घटनाओं से जोड़ते हैं। इन सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं को भारतीय भोजन, अनुभवी गाइड और आरामदायक परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।

पैकेज में तीन श्रेणियों की साझा व्यवस्था दी गई है—सिंगल ऑक्यूपेंसी 89,980, डबल ऑक्यूपेंसी 71,440 और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 70,070। बच्चों के लिए भी आयु के अनुसार अलग दरें तय की गई हैं। 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए पैकेज 35,480 रखा गया है। इस यात्रा की बुकिंग पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर होगी, और सीमित सीटों के कारण इच्छुक यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट पर तुरंत पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है।

धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक कनेक्टिविटी और ऐतिहासिक धरोहर को जोड़ने वाली यह यात्रा न केवल श्रद्धा का मार्ग है, बल्कि भारत और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करने का एक माध्यम भी है। रामायण के पावन प्रसंगों को प्रत्यक्ष अनुभव करने का यह दुर्लभ अवसर आने वाले वर्षों में रामायण सर्किट को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिमी सिंहभूम में दहशत की रात: आंगन की खटिया पर चादर के नीचे मिली वृद्ध दंपत्ति की लहूलुहान मौत ने हिला दिया पूरा इलाका

(जीएनएस)। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के शांत और निर्जन समझे जाने वाले लिपुंगा गांव में मंगलवार की सुबह ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर पूरे इलाके की रूह कांप उठी। 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू का लहूलुहान शव घर के आंगन की खटिया पर चादर ओढ़े मिला। जब ग्रामीणों ने सुबह उन्हें इस तरह लेटे देखा, तो शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन देर तक कोई हरकत न होने पर जब चादर हटाई गई, तो जो दृश्य सामने आया उसने गांव की नींद, शांति और भरोसे—सब कुछ तोड़ दिया।

दंपत्ति का गला धारदार हथियार से बेरहमी से काटा गया था। खून से भीगी खटिया, जमीन पर जमे धब्बे, और घर के भीतर पसरा सन्नाटा सब मिलकर इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या सोच-समझकर, रात की नीरवता में की गई थी। अपराधी हत्या के बाद सर्गिया और मुक्ता के शव को खाट पर लिटाकर चादर डाल गए, मानो उनके ज़िंदा रहने का कोई भ्रम बनाए रखना चाहते हों।

गांव वालों में भय और आक्रोश की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही गुवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्ज़े में लेकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के चेहरों पर सदमे का भय अब भी साफ दिख रहा था—एक ऐसे गांव में, जहां दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं और लोग बिना ताला लगाए निश्चिंत होकर सो जाते हैं, वहां इस तरह की घटना ने रातों की नींद छीन ली है। जांच में सामने आया कि बालमुचू दंपत्ति का कुछ समय पहले गांव के ही कुछ लोगों के साथ अंधविश्वास और डायन-बिसाही को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद कई बार इतना उग्र हो चुका था कि गांव में पंचायत तक बैठानी पड़ी थी। पुलिस को संदेह है कि यह दोहरा हत्याकांड उसी पुराने विवाद का नतीजा हो सकता है। डायन-बिसाही के नाम पर पहले भी झारखंड के कई इलाकों में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

गांव में पुलिस की टीमों ने चौकसी बढ़ा दी है। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी चल रही है और पुलिस दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि गांव में कई लोगों ने पिछली रात कुछ संदिग्ध आवाज़ें और हलचल देखे जाने की बात भी की है। ग्रामीणों में दहशत इतनी गहरी है कि लोग शाम होने से पहले ही घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं।

इस दर्दनाक घटना की गूंज इसलिए और अधिक भयावह हो उठती है क्योंकि झारखंड में एक हफ्ते के भीतर वृद्ध दंपत्ति की हत्या का यह दूसरा मामला है। खूंटी जिले में भी कुछ दिन पहले कानू मुंडा (66) और उनकी पत्नी गौरी देवी (64) की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

रांची की अदालत में पांच साल भटकता रहा 100 ग्राम गांजा का मामला, अंत में आरोपी को मिली सिर्फ 30 दिन की सजा-जो वह पहले ही काट चुका था

(जीएनएस)। झारखंड की राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न्यायिक प्रक्रिया की गति, जटिलताओं और वास्तविकता—तीनों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। महज 100 ग्राम गांजा मिलने के मामले में एक युवक पर दर्ज मामला पूरे पांच साल तक अदालत में चलता रहा, जबकि अंत में उसे सिर्फ 30 दिन की सजा दी गई—इतने ही दिन वह पहले ही जेल में बिता चुका था। फैसले के बाद अदालत ने तुरंत रिहाई का आदेश सुनाया और यह पूरा प्रकरण लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

यह कहानी शुरू हुई दिसंबर 2020 में, जब नगड़ी थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ चौक पर स्थित एक छोटे से पान दुकान पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यहां गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री होती है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करमटोली गांव निवासी विमल भगत की पान गुमटी पर छापेमारी की। जांच के दौरान दुकान से करीब 20 पुड़िया, कुल लगभग 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जब्ती सूची स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तैयार की और बाद में एफएसएल की रिपोर्ट में भी बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हो गई।

गिरफ्तारी के बाद विमल भगत को जेल भेजा गया, जहां वह लगभग 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहा और फिर जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ—न्यायालय में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज यह मामूली-सा दिखने वाला केस लगभग पाँच वर्ष तक चलता रहा। गवाहों की उपस्थिति, तारिखें, कागजी प्रक्रिया, बहस, फिर बहस की अगली तारीख इस सब के बीच आरोपी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट चुका था, लेकिन केस उसके सिर पर एक साये की तरह कायम रहा।

पांच साल बाद जब यह मामला विशेष एनडीपीएस अदालत में अंतिम चरण में पहुंचा, तो विशेष न्यायाधीश ओंकारनाथ चौधरी ने सुनवाई पूरी होने पर विमल भगत को दोषी तो करार दिया, लेकिन यह भी माना कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बरामद की गई मात्रा बेहद कम है, और वह 30 दिन पहले ही जेल में काट चुका है। इसलिए अदालत ने माना कि वही 30 दिन उसकी सजा के रूप में पर्याप्त हैं और तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया।

इस फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों ने यह भी खुलासा किया कि यदि विमल भगत ने सुनवाई के दौरान ही अपना दोष स्वीकार कर लिया होता, तो यह मामला पांच वर्षों तक नहीं खिंचता। अक्सर एनडीपीएस के छोटे मामलों में अपराध स्वीकार करने पर अदालत प्रक्रिया को तेज कर देती है और आरोपी को जल्द राहत मिल जाती है। लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उसे बेहद कम मात्रा में मिले गांजा के मामले में वर्षों तक ट्रायल का सामना करना पड़ा।

इस पूरी कहानी ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या ऐसे छोटे मामलों में अदालतों का समय, ऊर्जा और वर्षों का ट्रायल न्याय प्रणाली की वास्तविक समस्याओं का संकेत है? क्या छोटे मामलों को निपटाने के लिए एक तेज, सरल और त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए? और क्या आरोपी, जो पहली बार किसी मामले में फंसा हो, सुधार की राह पर जल्दी लौट सकता है? रांची का यह मामला दिखाता है कि कभी-कभी न्याय केवल सजा का नहीं बल्कि प्रक्रिया का नाम भी होता है—और उस प्रक्रिया का बोझ सजा से कई गुना भारी पड़ जाता है।